

I
A
S



P
C
S

THE TIMES OF INDIA

FRONTLINE

Prelims Capsule

प्रमुख अंग्रेजी अखबारों से...

THE TIMES OF INDIA

THE HINDU

The Indian EXPRESS

bridge terror

Corp. Office:-

629, Ground Floor, Main Road,
Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009
Ph.: - 011-27658013, 7042772062/63

जेलों की स्थिति पर सुप्रीम कोर्ट ने समिति बनाने का दिया आदेश

द हिन्दू/द वायर
(08 अगस्त)

संदर्भ-

- हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने देशभर की जेलों की खराब हालात पर चिंता जताते हुए एक समिति के गठन का आदेश दिया है।
- यह कदम पूरे देश में 1382 जेलों में प्रचलित अमानवीय स्थितियों से संबंधित अदालत में एक याचिका पर आधारित है।



समिति और इसके कार्य

- इस समिति में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर जज की एक सदस्यीय पीठ शामिल रहेंगे।
- इस समिति में एक सरकारी अधिकारी शामिल होगा, जो कि कमेटी का सहायक होगा।
- ये जेलों में महिला कैदियों और उनके बच्चों की स्थिति जांचेंगे और समय-समय पर जेल सुधारों को लेकर अपने सुझाव देंगे।
- नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) के आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न जेलों में महिला कैदियों के साथ उनके 1817 बच्चे भी रह रहे हैं।
- इससे पूर्व सुप्रीम कोर्ट ने वर्ष 2006 में जेल में महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चों की सुरक्षा व जीवनस्तर के बारे में कई दिशानिर्देश दिए थे।



आरसीईपी मुद्दों को जांचने के लिए मंत्रिस्तरीय समूह की स्थापना

फाइनेंसियल एक्सप्रेस, इकॉनॉमिक टाइम्स
(07 अगस्त)

संदर्भ-

- हाल ही में केंद्र सरकार ने वाणिज्य और उद्योग मंत्री सुरेश प्रभु की अध्यक्षता में चार सदस्यीय मंत्रिपरिषद (GoM) का गठन किया है।

उद्देश्य-

- GoM का गठन प्रधानमंत्री मोदी को यह सलाह देने के लिए किया गया है कि उन्हें 16 सदस्यीय क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) वार्ता को आगे बढ़ाया जाए या उसे बर्खास्त कर दिया जाए।
- GoM में वित्त और ऊर्जा मंत्री पियूष गोयल, रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण और आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी भी शामिल हैं।
- यह बैठक यह निर्धारित करेगी कि क्या भारत इन देशों में मुक्त व्यापार के लिए 92% बाजार पहुंच प्रदान करने के लिए इच्छुक है या नहीं।
- व्यापार संधि इस्पात, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि, इलेक्ट्रॉनिक्स, भारी उद्योग, कपड़ा और रसायनों के क्षेत्रों को प्रभावित करेगी क्योंकि घरेलू बाजारों को प्रभावित करने वाले चीनी उत्पादों का प्रवाह होगा।
- नवंबर, 2018 में जापान, चीन, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया समेत सदस्य देशों के साथ आरसीईपी शिखर सम्मेलन में आने वाली व्यापार वार्ताओं से पहले ये वार्ता आयोजित होगी।
- इसके अलावा 16 सदस्यीय आरसीईपी मंत्रिस्तरीय बैठक सिंगापुर में 30 और 31 अगस्त को है।





क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP)

- यह एक मेगा मुक्त व्यापार समझौता (FTA) है।
- इसमें एशिया-प्रशांत क्षेत्र के 16 देश शामिल हैं।
- इसका उद्देश्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिये इसके सदस्य देशों के बीच व्यापार नियमों को उदार एवं सरल बनाना है।
- आरसीईपी या क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी, दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ (आसियान) के दस सदस्यीय देशों तथा छः अन्य देशों (ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड), जिनके साथ आसियान का मुक्त व्यापार समझौता है, के बीच प्रस्तावित मुक्त व्यापार समझौता है।
- इसकी औपचारिक शुरुआत नवंबर 2012 में कंबोडिया में आसियान शिखर सम्मेलन में की गई थी।
- आरसीईपी को ट्रांस-पैसिफिक भागीदारी के एक विकल्प के रूप में देखा जाता है।

कंचनजंगा यूनेस्को की बायोस्फियर रिजर्व सूची में शामिल

द हिन्दू, टाइम्स ऑफ इंडिया
(10 जुलाई)

संदर्भ-

- हाल ही में दुनिया के सबसे ऊंचे ईकोसिस्टम्स में से एक सिक्किम के कंचनजंगा बायोस्फियर रिजर्व को यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फियर रिजर्व (डब्लूएनबीआर) की सूची में शामिल कर लिया गया है।
- कंचनजंगा इस सूची में शामिल होने वाला भारत का 11वां बायोस्फियर रिजर्व है।



- इसे यूनेस्को की इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग काउंसिल (आइसीसी) ऑफ मैन एंड बायोस्फियर (एमएबी) प्रोग्राम की 30वीं बैठक में कंचनजंगा बायोस्फियर रिजर्व को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फियर रिजर्व में शामिल किया गया है।
- इससे पहले नंदादेवी, सिमलीपाल, सुंदरवन और नीलगिरी जैसे बायोस्फियर को इस सूची में शामिल किया जा चुका है।
- भारत में 18 बायोस्फियर रिजर्व हैं।
- देश के 18 बायोस्फियर में से 11 को डब्लूएनबीआर की सूची में शामिल किया जा चुका है।
- इस सूची में शामिल होने वाला भारत का पहला बायोस्फियर रिजर्व तमिलनाडु का नीलगिरी था, जिसे वर्ष 2000 में शामिल किया गया था।

जैवमंडल-

- जैवमंडल से तात्पर्य पृथ्वी के उस भाग से है जहां सभी प्रकार का जीवन पाया जाता है।
- पृथ्वी के तीन परिमंडल-स्थलमंडल, वायुमंडल और जैवमंडल जहाँ आपस में मिलते हैं, वहीं जैवमंडल स्थित है। इस जैवमंडल की परत बेहद पतली, लेकिन अत्यधिक जटिल है।

Khangchendzonga National Park



- किसी भी प्रकार का जीवन जैवमंडल की इसी परत में संभव है, क्योंकि इसके लिए आवश्यक भूमि, हवा और जल केवल इन तीनों मंडलों के मिलन क्षेत्र अर्थात जैवमंडल में ही मौजूद है।

इज ऑफ लिविंग इंडेक्स

फाइनेंसियल एक्सप्रेस, इकॉनॉमिक टाइम्स
(08 अगस्त)

संदर्भ-

- यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय (एमओएचयूए) की एक पहल है।
- यह शहरों को वैश्विक और राष्ट्रीय मानकों के साथ-साथ रहने की योग्यता का आकलन करने में मदद करेगी।



ज्वार फसलों का दुश्मन आर्मी वर्म भारत पहुंचा

द हिन्दू
(10 अगस्त)

संदर्भ

- हाल ही में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की रिपोर्ट के अनुसार कर्नाटक के चिक्काबालापुर जिले में आर्मी वर्म पाया गया है।
- कर्नाटक में इसकी मौजूदगी एशिया में पहली घटना है।
- इसने यहां की 70 फीसदी ज्वार की फसल को अपना निशाना बनाया है और यह सब्जियों तक पहुंच चुका है।
- इस कीट का मुख्य भोजन ज्वार की फसल होती है।

आर्मी वर्म

- इसका अंग्रेजी में आर्मी वर्म और वैज्ञानिक नाम स्पोडोप्टेरा फ्रूजीपेडा है।
- इसके अलावा यह 186 तरह के पौधों की प्रजातियों को भी अपना निवाला बनाता है।
- पिछले दो वर्षों में अफ्रीका में ज्वार, सोयाबीन आदि की फसल के नष्ट हो जाने से अरबों पाउंड का नुकसान हुआ।

पृष्ठभूमि

- यह उत्तरी अमेरिका में एक प्रमुख मक्का कीट है और यह 2016 में अफ्रीका पहुंचा।
- यह 2016 में मध्य और पश्चिमी अफ्रीका में फैल गया है और इसे नियंत्रित करने में बहुत मुश्किल साबित हुई है।
- यह मक्का पसंद करता है, लेकिन चावल, ज्वार, बाजरा, गन्ना और कपास सहित पौधों की 80 प्रजातियों को भी नुकसान पहुंचा सकता है।
- भारत का उष्णकटिबंधीय जलवायु इस कीट के उपयुक्त स्थान है।
- इसे प्राकृतिक दुश्मनों के माध्यम से या अंतर-फसल द्वारा कीटनाशकों के साथ नियंत्रित किया जा सकता है।



- इसने चार स्तंभों जैसे कि संस्थागत, सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक आधार पर 111 शहरों को रैंक प्रदान किया है।
- यह इज ऑफ लिविंग मूल्यांकन के मानकों पर आधारित है जो सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) से निकटता से जुड़े हुए हैं।
- यह शहरों को शहरी नियोजन और प्रबंधन के लिए 'परिणाम-आधारित' दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।
- इसे स्वच्छ भारत मिशन स्वच्छ सर्वेक्षण 2019 के हिस्से के रूप में लॉन्च किया जा रहा है।

स्वच्छ मंच वेब पोर्टल-

- केंद्र सरकार स्वच्छ मंच पोर्टल नामक एक और पहल भी शुरू करेंगे।
- यह एक वेब-आधारित प्लेटफॉर्म है जो एक सामान्य मंच के तहत स्वच्छ भारत मिशन की ओर योगदान करने के लिए प्रत्येक हितधारक को एक साथ लाएगा।
- यह मंच हितधारकों को उनके पड़ोस के आस-पास विभिन्न स्वयंसेवी अवसरों को बनाने, आमंत्रित करने और भाग लेने की अनुमति देगा।
- सभी नागरिक और भाग लेने वाले संगठन अब इस स्वच्छ मंच पोर्टल पर फोटो सबूत अपलोड कर सकते हैं।
- इस पोर्टल में नागरिकों के स्वयंसेवकों की संख्या के रिकॉर्ड भी शामिल होंगे।
- यह "स्वच्छता" के कारण नागरिकों/संगठनों की स्वीकृति के रूप में कार्य करेगा।
- स्वच्छ मंच पोर्टल पहले से ही मौजूदा स्वच्छता ऐप के साथ एकीकृत किया जा रहा है।
- यह शिकायतें सुनने और लोगों को समाधान प्रदान करने के लिए नागरिक शिकायत निवारण मंच के रूप में कार्य करेगा।



स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

Swachh Manch
Web Portal
Launch

Swachh Survekshan
2019

newsbottom.com



सरकार ने निर्यात मित्र ऐप लॉन्च की

टाइम्स ऑफ इंडिया
(08 अगस्त)

संदर्भ-

- हाल ही में केन्द्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय ने आयातक व निर्यातकों के लिए निर्यात मित्र मोबाइल ऐप लांच की।
- निर्यात मित्र ऐप एंड्रॉयड और iOS दोनों प्लेटफॉर्म पर काम करेगी।
- इस ऐप को भारतीय निर्यात संगठन संघ ने विकसित किया है।
- यह देश का सबसे बड़े निर्यात संगठन है।

उद्देश्य-

- इसकी मदद से देश में निर्यात का एक माहौल तैयार होगा जो कारीगरों, कुटीर उद्योग एवं सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यमियों को निर्यात के लिए प्रोत्साहित करेगा।

निर्यात मित्र ऐप-

- इस ऐप में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सम्बन्ध में काफी विस्तृत जानकारी है, इसमें आयात व निर्यात के लिए नीति व्यवस्था, GST रेट, निर्यात प्रोत्साहन राशि, शुल्क इत्यादि की विस्तृत जानकारी दी गयी है।
- इसमें टेरिफ लाइन के सम्बन्ध में भी जानकारी दी गयी है।
- वर्तमान में इस ऐप में 87 देशों का डाटा उपलब्ध है।
- यह ऐप भारतीय निर्यात संगठन संघ के प्रोग्राम के बारे में भी जानकारी उपलब्ध करवाती है।

भारतीय निर्यात संगठन संघ-



- भारतीय निर्यात संगठन संघ देश के सबसे बड़े व्यापार संगठनों में से एक है।
- इसकी स्थापना 1965 में वाणिज्य मंत्रालय और निजी व्यापार व उद्योगों द्वारा संयुक्त रूप से किया गया था।
- यह 1860 के सोसायटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत पंजीकृत है।

- संगठन विदेशी उद्यमों में भारतीय उद्यमियों और निर्यातकों का प्रतिनिधित्व और सहायता करने के लिए जिम्मेदार है।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है।



- यह संगठन भारतीय उद्यमियों और निर्यातकों का विदेश में प्रतिनिधित्व व सहायता करता है।

राष्ट्रपति कोविंद ने 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' समिट का शुभारंभ किया

टाइम्स ऑफ इंडिया, फाइनेंसियल एक्सप्रेस
(11 अगस्त)

संदर्भ-

- हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने प्रदेश की सरकार की तरफ से आयोजित तीन दिवसीय 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' (ओडीओपी) अर्थात एक जनपद-एक उत्पाद समिट का शुभारंभ किया।
- राष्ट्रपति ने 75 जिलों के उत्पादों की प्रदर्शनी देखी और व्यापारियों को 1,006 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान किया।
- ओडीओपी मूल रूप से एक जापानी व्यापार विकास अवधारणा है, जिसे 1979 में प्रसिद्धि मिली।



उद्देश्य-

- बिक्री को बढ़ाना और स्थानीय आबादी के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए एक विशिष्ट क्षेत्र से प्रतिस्पर्धी और प्रमुख उत्पाद को बढ़ावा देना है।
- समय के साथ, इसे अन्य एशियाई देशों में भी दोहराया जा चुका है।
- प्रदेश में इस समय 8,900 करोड़ रुपये के उत्पाद का ही निर्यात होता है जिसे बढ़ाकर 2 लाख करोड़ करने का लक्ष्य रखा गया है।



अन्य तथ्य-

- यूपी के 75 जिले उत्पाद-विशिष्ट पारंपरिक औद्योगिक केंद्रों के लिए विशिष्ट रूप से प्रसिद्ध है।
- जिसमें वाराणसी (बनारसी रेशम साड़ी), भदोही (कालीन), लखनऊ (चिकन), कानपुर (चमड़े के सामान), आगरा (चमड़े के जूते), अलीगढ़ (ताले), मुगदाबाद (पीतल के बर्तन), मेरठ (खेल सामग्री) और सहारनपुर (लकड़ी के उत्पाद) शामिल है।



1. हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के आदेश से जेलों में सुधार पर बनने वाली समिति के कार्यों में निम्नलिखित में से शामिल है-
 - (a) जेलों में महिला कैदियों की स्थिति की जाँच करना।
 - (b) समय-समय पर जेलों में सुधार के लिए सुझाव देना।
 - (c) जेल में महिला कैदियों के साथ रहने वाले बच्चों की जाँच करना।
 - (d) उपर्युक्त सभी
2. क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (आर.सी.ई.पी.) के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन-से कथन सत्य हैं?
 1. यह एक मेगा मुक्त व्यापार समझौता है, जिसमें एशिया प्रशांत क्षेत्र के देश शामिल हैं।
 2. भारत इसमें भागीदारी पर विचार करने के लिए चार सदस्यीय समिति का गठन किया है।
 3. इसका उद्देश्य सदस्य देशों के मध्य व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए व्यापार नियमों को सरल एवं उदार बनाना है।

नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनिए-

 - (a) 1 और 2
 - (b) 2 और 3
 - (c) 1 और 3
 - (d) 1, 2 और 3
3. कंचनजंगा बायोस्फियर रिजर्व के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
 1. यह विश्व का सबसे ऊँचाई पर स्थित रिजर्व है, जिसे हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फियर रिजर्व में शामिल किया गया है।
 2. यह भारत का 11वाँ रिजर्व है, जो यूनेस्को की वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फियर रिजर्व में शामिल किया गया है।

उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?

 - (a) केवल 1
 - (b) केवल 2
 - (c) 1 और 2 दोनों
 - (d) न तो 1 और न ही 2
4. हाल ही में जारी 'इज ऑफ लिविंग इंडेक्स' से निम्नलिखित में से क्या लाभ हो सकता है?
 - (a) यह शहरों को वैश्विक और राष्ट्रीय मानकों के साथ-साथ रहने की योग्यता के आकलन में सहायक होगा।
 - (b) यह सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) को प्राप्त करने में सहायक होगा।
 - (c) इससे शहरों को शहरी नियोजन और प्रबंधन के लिए परिणाम आधारित दृष्टिकोण की ओर बढ़ने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
 - (d) उपर्युक्त सभी।
5. हाल ही में पाया गया कीट निम्नलिखित में से कौन-सा है, जिसने ज्वार की फसलों को बहुत हानि पहुँचाया है?
 - (a) आर्मी वर्म
 - (b) सफेद गिडार
 - (c) अरली ब्लाइट ऑफ ज्वार
 - (d) आर्मी जैथोमोनास
6. निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
 1. 'निर्यात मित्र ऐप' जिसे आयातक-निर्यातक के लिए केंद्रीय वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किया गया है।
 2. निर्यात मित्र ऐप का उद्देश्य कारीगरों, कुटीर उद्योग एवं सूक्ष्म लघु एवं मझोले उद्यमियों को निर्यात के लिए प्रोत्साहित करना है।
 3. निर्यात मित्र ऐप भारतीय निर्यात संगठन संघ के प्रोग्राम के बारे में सूचना उपलब्ध कराता है।

नीचे दिए गए कूट के प्रयोग से सही उत्तर चुनिए-

 - (a) 1 और 2
 - (b) केवल 2
 - (c) 2 और 3
 - (d) 1, 2 और 3
7. 'एक जनपद-एक उत्पाद' योजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से क्या असत्य है?
 - (a) इस योजना का सर्वप्रथम प्रयोग जापान में किया गया था, जो अभी उत्तर प्रदेश में प्रारम्भ की गई है।
 - (b) इसका उद्देश्य एक विशिष्ट क्षेत्र से प्रतिस्पर्धा और प्रमुख उत्पाद को बढ़ावा देना है।
 - (c) इसके अंतर्गत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 लाख करोड़ रूपए के उत्पाद का निर्यात करने का लक्ष्य रखा गया है।
 - (d) यह एक केंद्रीय स्तर पर चलायी गई योजना है, जिसे कई भारतीय राज्यों द्वारा अपनाये जाने के बाद उत्तर प्रदेश में लागू की गई है।

नोट-

10 अगस्त को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संबंधित प्रश्न) का उत्तर 1. (b), 2. (c), 3. (b), 4. (b), 5. (a) होगा।